पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,

2015 की विविध अपील सं॰ 149

==========

मेसर्स ए. सी. सी. लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कार्यालय समृद्धि परिसर, एस. पी. वर्मा रोड, पी. एस. गांधी मैदान, जिला-पटना (बिहार) द्वारा अपने कर प्रभारी एस. यू. पटना सुश्री अदिति अवस्थी के माध्यम से है।

.... याचिकाकर्ता/अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार, पटना
2. संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना
3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष सर्कल, पटना
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष सर्कल, पटना

.... प्रतिवादीगण/

==========

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट कर अधिनियम)-- धारा 39 (4)-उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993 (प्रवेश कर अधिनियम)-- धारा 3 (1) के प्रावधान, धारा 3 (2), के प्रावधान-वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार द्वारा वैट दायित्व के खिलाफ क्षतिग्रस्त सीमेंट पर भुगतान किए गए प्रवेश कर के समायोजन से इनकार-प्रवेश कर अधिनियम के तहत क्षतिग्रस्त सीमेंट पर प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी का दायित्व-धनवापसी या वापसी के लिए अपीलार्थी का अधिकार वैट अधिनियम के तहत ब्याज लगाने की समायोजन-वैधता।

आयोजित किया गयाःवाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार के आदेश से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया गया-निर्धारिती द्वारा अपील विफल-प्रत्यर्थियों के पक्ष में निर्धारिती के खिलाफ कानूनी प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,

2015 की विविध अपील सं॰ 149

==========

मेसर्स ए. सी. सी. लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कार्यालय समृद्धि परिसर, एस. पी. वर्मा रोड, पी. एस. गांधी मैदान, जिला-पटना (बिहार) द्वारा अपने कर प्रभारी एस. यू. पटना सुश्री अदिति अवस्थी के माध्यम से है।

.... याचिकाकर्ता/अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य द्वारा प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार, पटना
2. संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), केंद्रीय प्रभाग, पटना
3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष सर्कल, पटना
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष सर्कल, पटना

.... प्रतिवादीगण/

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी के लिए : श्री रमेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता

श्री शिव कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अजय बिहारी सिन्हा, जी. ए. 8

श्री विकास कुमार, एससी 11

सुश्री कल्पना, जी. ए. 8 की एसी

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

कैव निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीखः 30-11-2023

वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, बिहार (अब से संक्षिप्त में, 'न्यायाधिकरण') के आदेश से उत्पन्न उपरोक्त अपील में आदेश सं० 6 दिनांकित 27.07.2015 द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न निम्नलिखित हैंः-

"(I) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, 'न्यायाधिकरण' को वैट देयता के खिलाफ क्षतिग्रस्त सीमेंट पर भुगतान किए गए प्रवेश कर के समायोजन से इनकार करना उचित था?

(II) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, अपीलार्थी प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षतिग्रस्त सीमेंट पर प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और क्या अपीलार्थी धनवापसी या उसके समायोजन का हकदार नहीं है?

(III) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, वैट अधिनियम की धारा 39 (4) के तहत ब्याज का अधिरोपण मनमाना, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है?"

2. जिन तथ्यों पर कानून के उपरोक्त प्रश्न उठते हैं, वे इस प्रकार हैंः- अपीलार्थी अपनी विभिन्न बिक्री इकाइयों के माध्यम से देश भर में सीमेंट का निर्माण और

बिक्री करता है, जिनमें से एक पटना में स्थित है और अपीलार्थी बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, 'वैट अधिनियम') के तहत एक पंजीकृत विक्रेता भी था। अपीलार्थी बिहार राज्य के बाहर से स्टॉक हस्तांतरण के माध्यम से राज्य में सीमेंट का आयात करता है और सीमेंट को राजधानी शहर के भीतर और राज्य के अन्य जिलों में भी बेचा जाता है। बिहार में सीमेंट के भंडारण के लिए राज्य के विभिन्न शहरों में स्थित पंद्रह गोदामों के लिए आठ सी एंड एफ एजेंट नियुक्त किए गए हैं।

3. मूल्यांकन वर्ष 2010-11 में, अपीलार्थी ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित अपनी विनिर्माण इकाइयों से राज्य में 10,12,535.90 मीट्रिक टन सीमेंट का आयात किया। रेलवे और को भुगतान किए गए माल सी एंड एफ अभिकर्ताओं को भुगतान किये गये कमीशन के अलावा प्रवेश कर का भी भुगतान किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग के लेखापरीक्षा दल (अब से संक्षिप्त में 'विभाग') ने पाया कि निर्धारिती ने वार्षिक विवरणी के साथ-साथ टी. ए. आर. में राज्य के बाहर से स्टॉक हस्तांतरण मूल्य 45,12,63,567.00 रुपये दिखाया था और ई. टी.-V (प्रवेश कर भुगतान) में दिखाया गया कुल आयात मूल्य 527,56,05,041.00 रुपये था, इस प्रकार यह मूल्य 76,29,71,474.00 रुपये छिपा रहा था। यह भी पाया गया कि क्षतिग्रस्त सीमेंट पर भुगतान किए गए प्रवेश कर का समायोजन उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993 (संक्षिप्तता के लिए, 'प्रवेश कर अधिनियम') के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं था।

4. मामला 'न्यायाधिकरण' के पास गया जिसने माल ढुलाई और कमीशन के सवाल पर मामले को मूल्यांकन अधिकारी को दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए भेज दिया ताकि लिए गए तर्क को साबित किया जा सके। जहां तक क्षतिग्रस्त सीमेंट पर भुगतान किए गए प्रवेश कर का संबंध है, 'न्यायाधिकरण' ने पाया कि इसे वैट देयता से समायोजित

नहीं किया जा सकता है, प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) के प्रावधान की परिस्थितियों में वैट अधिनियम के तहत देय कर में इस तरह की कमी का प्रावधान किया गया है, जब अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी आयातित माल राज्य के भीतर कर देयता को वहन करता है। क्षतिग्रस्त माल पर कोई कर देयता नहीं थी, इसलिए इस तरह के क्षतिग्रस्त माल पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की सीमा तक वैट देयता में कोई कमी नहीं होगी; जिससे अपील में कानून के सवाल उठते हैं।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने ***हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम् बिहार राज्य; (2004) 136 एस. टी. सी. 396*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर तर्क दिया कि प्रवेश कर भुगतान किया गया कर निर्धारिती के कुल वैट दायित्व से कम होने का हकदार होगा, विशेष रूप से जब क्षतिग्रस्त माल राज्य के भीतर नहीं बेचा गया था। ***एच.एम.एम. लिमिटेड बनाम् प्रशासक, बैंगलोर नगर निगम; (1989) 4 एस. सी. सी. 640*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी यह तर्क देने के लिए भरोसा किया जाता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर या शुल्क नहीं लगाया जा सकता है और वर्तमान मामले में, निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई के परिणामस्वरूप उन वस्तुओं पर कर लगाया गया है जिन्हें बिहार राज्य के भीतर बेचा या उपभोग नहीं किया गया है, इस प्रकार प्रवेश कर अधिनियम के तहत लेवी, कानून के अधिकार के बिना एक है।

6. ***एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (2004) 7 एस. सी. सी. 642*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है। इसमें वहाँ होने के बावजूद बिहार राज्य के भीतर बेचे जाने वाले माल के लिए कर का कोई दायित्व नहीं है, जो राज्य के बाहर से आयात किया गया था, आयात के समय भुगतान किया गया प्रवेश कर को निर्धारिती के कुल दायित्व से कम करने की अनुमति दी गई थी। विद्वान

वकील ने ***मेसर्स श्री शंकर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज बनाम बिहार राज्य, सी.डब्ल्यू.जे.सी 19512/2010*** में इस न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले को भी रखा।

7. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता, श्री विकास कुमार ने विशेष रूप से क़ानून में प्रयुक्त शब्दों पर भरोसा करते हुए 'न्यायाधिकरण' के आदेश का समर्थन किया। यह बताया गया है कि क्षतिग्रस्त माल का निपटान कैसे किया गया, इसके बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त माल को विनिर्माण इकाई को वापस कर दिया जाएगा, जिस स्थिति में निर्धारिती धनवापसी का दावा कर सकता था। राज्य का कहना है कि अपील खारिज की जा सकती है और कानून का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ***राज्य ने इंडियन ऑयल निगम बनाम बिहार राज्य 2018 (1) एससीसी 242*** पर भरोसा किया।

8. प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (1) नाममात्र शीर्षक 'कर प्रभार' के साथ, राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विकास के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर ऐसे माल के आयात मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक की दर से कर लगाती है। धारा 3 (1) का दूसरा परंतुक इस प्रकार हैः-

> *"बशर्ते कि यदि कोई आयातक यह दावा करता है कि उसने उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित वस्तुओं का आयात उपभोग, उपयोग या बिक्री के उद्देश्य से नहीं किया है, तो यह साबित करने का बोझ कि आयात उपभोग, उपयोग या बिक्री के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए था, आयातक पर होगा जो ऐसी वस्तुओं का आयात करता है और ऐसा दावा करता है।"*

9. धारा 3 की उप-धारा (2) आगे वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाती है;

जो बिहार राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूचित वस्तुओं का आयात करता है, चाहे वह अपने खाते में हो या अपने मूलधन के कारण या डिलीवरी लेता है या प्रवेश कर अधिनियम के तहत देय कर के लिए ऐसी वस्तुओं की डिलीवरी लेने का हकदार है। धारा 3 की उप-धारा (2) का दूसरा परंतुक भी यहाँ इस प्रकार उद्धृत किया गया हैः-

> *"बशर्ते कि जहां अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अनुसूचित वस्तुओं का कोई आयातक, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 के तहत निर्दिष्ट दर पर, आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री या ऐसी आयातित अनुसूचित वस्तुओं का उपभोग करके निर्मित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर कर देयता वहन करता है, तो बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) के तहत उसकी कर देयता इस अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगीः"*

10. उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या यहाँ विवाद को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 3 (1) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि निर्धारिती अनुसूचित माल का आयात करता है, यह तर्क है कि इसका आयात उपभोग, उपयोग या बिक्री के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा था, उक्त तथ्य को साबित करने का बोझ आयातक पर है। उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक में यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित वस्तुओं के आयातक द्वारा प्रवेश कर का भुगतान करने पर, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है, जब वह वैट अधिनियम के तहत दायित्व वहन करता है, तो ऐसी देयता प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी। वैट देनदारी के तहत छूट केवल तभी उत्पन्न होगी जब उस अधिनियम के तहत कोई

देनदारी होगी और राज्य के भीतर कोई खपत, उपयोग या बिक्री नहीं होने की स्थिति में, आयातक को यह साबित करना होगा कि माल का निपटान कैसे किया गया था।

11. उपरोक्त दो आकस्मिकताएँ दो अलग-अलग और विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जिन्हें किसी भी तरह से मिश्रित नहीं किया जा सकता है। यदि माल का आयात राज्य के भीतर उपभोग, उपयोग या बिक्री के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो आयातक को यह साबित करना होगा कि आयातित माल का निपटान कैसे किया गया था। यदि माल, जिस रूप में आयात किया गया था या किसी अन्य रूप में, वैट अधिनियम के तहत एक देयता थी, तो प्रवेश पर भुगतान किया गया कर वैट अधिनियम के तहत किए गए देयता से कम हो जाएगा। अपीलार्थी न तो दलील देता है लेकिन दावा करता है; हालाँकि सीमेंट को बिक्री के लिए आयात किया गया था, यह क्षतिग्रस्त हो गया था और इसे बेचा नहीं जा सका था और यह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त सीमेंट का क्या हुआ।

12. ***हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (ऊपर)*** एक ऐसा मामला था जिसमें निर्धारिती के पास बिहार राज्य के भीतर सी एंड एफ एजेंट थे और उन्होंने राज्य के भीतर दो स्थानीय क्षेत्रों से सामान (हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल) खरीदा और इसे पटना स्थानीय क्षेत्र में लाया जहां से इसे अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यक्तियों को बेचा जाता था और स्टॉक को राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जाता था। निर्धारिती ने इस आधार पर छूट का दावा किया कि पटना स्थानीय क्षेत्र के भीतर माल का उपभोग, उपयोग या बिक्री नहीं की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत शुल्क केवल तभी लगाया जाएगा जब माल को स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, न कि जब इसे बाहर निकालने और उपभोग करने या अन्य स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग करने का इरादा होता है। तब भी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह विक्रेता

को निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित करना है कि बिक्री माल को बाहर निकालने या फिर से निर्यात करने के उद्देश्य से थी, न कि स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग या उपयोग के उद्देश्य से।

13. ***एच. एम. एम. लिमिटेड (उपरोक्त)*** भी नगरपालिका सीमा के भीतर 'उपभोग, उपयोग या बिक्री' के लिए लाए गए माल के प्रवेश पर चुंगी लगाने का मामला था। उसमें निर्धारिती ने छोटी इकाइयों में पुनः पैकिंग के लिए और नगरपालिका सीमा के बाहर निर्यात करने के लिए थोक में नगरपालिका क्षेत्र में सामान लाया। यहाँ, निर्धारिती के पास ऐसा कोई विवाद नहीं है और उपरोक्त उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। ***एच. एम. एम. लिमिटेड (ऊपर उल्लिखित)*** के इस कथन पर कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर या शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधिकार की अनुपस्थिति या कमी को कर के साथ जुड़े परिचर तथ्यों से पाया जाना चाहिए, जो कर कानून से निकलते हैं।

14. ***एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड (ऊपर)*** ने पूर्ववर्ती बिहार राज्य में दो विनिर्माण इकाइयाँ और अतिरिक्त/वृद्धिशील उत्पादन के साथ नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को कर छूट की एक प्रोत्साहन योजना के आधार पर, कंपनी ने वृद्धिशील उत्पादन के लिए धन का निवेश किया; जिसके लिए कंपनी को 1998 से 2007 की अवधि के बीच बिक्री कर से छूट दी गई थी। निर्धारिती ने कर की कुल देनदारी से भुगतान किए गए पूरे प्रवेश कर को समायोजित करने के अधिकार पर जोर देते हुए तर्क दिया कि जिन वस्तुओं पर कर लगाया गया था और जिन्हें भुगतान से छूट दी गई थी, उनका विभाजन कानूनी रूप से अनुमत नहीं था। जबकि, राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि छूट के आधार पर कोई देयता नहीं है, इसलिए भुगतान किए गए प्रवेश कर का कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है।

15. हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि, वित्तीय संदर्भ में शाब्दिक रूप से 'छूट' दायित्व से मुक्ति है, वित्तीय संदर्भ में, यह अलग-अलग आकार धारण करता है और इसलिए, एक छूट अधिसूचना के संदर्भ में 'देयता' शब्द माना जाता है। वैधानिक प्रावधानों से यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रभार अनुभाग बिक्री कर के भुगतान का प्रावधान करता है जबकि एक अन्य प्रावधान राज्य सरकार को इस तरह के भुगतान से छूट देने का अधिकार देता है। कर का भुगतान करने की देयता और कर का वास्तविक भुगतान वैचारिक रूप से अलग माना जाता था। छूट अधिसूचना प्रभार अनुभाग द्वारा सृजित दायित्व को समाप्त नहीं करती है, बल्कि केवल निर्धारिती को कर का भुगतान करने से मुक्त करती है, यह निर्धारिती के पक्ष में दिया गया निष्कर्ष था।

16. यह इस मामले के तथ्यों में अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आता है क्योंकि छूट का कोई सवाल नहीं उठाया गया है और अप्रमाणित संस्करण यह है कि इतना माल क्षतिग्रस्त हो गया था और इसलिए बेचा नहीं गया था और इस प्रकार कोई दायित्व नहीं लिया गया था। वास्तव में, उद्धृत निर्णय के कथन के अनुसार, जब तक कि कर के लिए कोई देयता नहीं है, प्रवेश कर का कोई समायोजन नहीं हो सकता है और तत्काल मामले में, उपरोक्त कथन के अनुसार छूट के लिए अपीलार्थी का दावा विफल हो जाता है।

17. ***श्री शंकर बर्फ और शीत भंडारण (ऊपर)*** में निर्धारिती ने स्थानीय क्षेत्र में आयातित पात्रों के लिए प्रवेश कर की मांग को इस आधार पर चुनौती दी कि यह सूखे मेवों से भरा था। और बिहार राज्य के बाहर निर्यात किया जाता था। खण्ड पीठ ने पाया कि कंटेनर सूखे मेवों से भरे हुए थे, जिनका सेवन और उपयोग राज्य में किया जाता था और इसलिए प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी था। यह किसी भी तरह से अपीलार्थी की मदद नहीं करता है क्योंकि वे पहले ही प्रवेश कर का भुगतान कर चुके हैं, जो देयता स्वीकार की जाती है, और इसके कुल बिक्री कर देयता में समायोजन या कटौती के लिए आगे का दावा, यहाँ

आग्रह किया गया प्रश्न है। उद्धृत निर्णय में केवल प्रवेश कर अधिनियम के तहत देयता पर विचार किया गया है न कि आगे के सेट-ऑफ पर, जो विशिष्ट शर्तों के अधीन है।

18. ***इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर)*** प्रवेश कर के निर्धारण से निपटने के लिए इस बिन्दु पर एक मामला है, जब आयातित माल को आयातक के हाथों बिहार राज्य के भीतर कर के लिए आगे दायित्व का सामना नहीं करना पड़ा। उसमें निर्धारिती ने बिहार राज्य के बाहर से कच्चे तेल का आयात किया, राज्य के भीतर अपनी रिफाइनरी में उच्च गति वाले तेल, पेट्रोल आदि का निर्माण किया और इसे पटना में अपनी शाखा में स्थानांतरित कर दिया, जहां से इसे अन्य तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को बेचा गया, जो बदले में इसे खुदरा विक्रेताओं को बेचते थे, पटना के अंदर और बाहर अपने स्वयं के पेट्रोलियम आउटलेट के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचते थे। जिनकी बिक्री निर्धारिती द्वारा भी की गई थी। की अधिसूचना के बाद से बिहार वित्त अधिनियम, 2005 के तहत ओ. एम. सी. को की गई बिक्री पर कर नहीं लगाया गया। ओ. एम. सी. को बेचे जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों पर कर लगाने के बिंदु को खुदरा विक्रेताओं और अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी बिक्री के बिंदु पर स्थानांतरित कर दिया गया था। अपीलार्थी ने 16 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का भुगतान किया और वह बिक्री कर @ 24.5% के लिए उत्तरदायी था, जिसमें से कुल देयता, सेट-ऑफ का दावा किया गया था और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था; जो बाद में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही को जन्म देते हुए उलट गया। प्रावधानों के प्रचुर संदर्भ के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में ऐसा अभिनिर्धारित कियाः

> **"13.** चूँकि विचाराधीन भुगतान प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) की व्याख्या पर निर्भर करता है, इसलिए शुरुआत में यह बताना

आवश्यक है कि उक्त प्रावधान के बिना भुगतान करने के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 3 (2) के तहत ही, प्रवेश कर के रूप में देय कर का भुगतान केवल वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता द्वारा किया जा सकता है।

(ii) छूट केवल तभी दी जा सकती है जब निर्धारिती अनुसूचित वस्तुओं का आयातक हो, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो।

(iii) निर्धारिती को वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कर देयता वहन करनी चाहिए।

(iv) यह केवल आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए; और

(v) वैट अधिनियम के तहत "उसकी" कर देयता तब अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी।

19. वित्त अधिनियम के तहत एक पंजीकृत विक्रेता होने के नाते निर्धारिती को पहली शर्त को पूरा करते हुए पाया गया और हालांकि निर्धारिती माल का आयातक था, लेकिन तेल विपणन कंपनियों को अपनी बिक्री पर वैट का भुगतान करने का उसका कोई दायित्व नहीं था, इस प्रकार वह दूसरी और तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर सका। निर्धारिती ने चौथी शर्त को भी संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि प्रावधान में प्रयुक्त शब्द; 'या ऐसे आयातित उपभोग द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री अनुसूचित वस्तु 'जो आयातक द्वारा ही की गई

बिक्री को दर्शाती है, जो अकेले पाँचवीं शर्त के अनुसार बंद करने का हकदार है। यह उक्ति उस तत्काल मामले में पूरी तरह से लागू होती है जहां अपीलार्थी-निर्धारिती को बिहार राज्य के भीतर आयातित वस्तुओं पर कर नहीं देना पड़ा था, इस प्रकार अपीलार्थी को ऐसे आयातित सामानों की सीमा तक, जिन पर बिहार राज्य के भीतर कर नहीं लगाया गया था, जमा करने का दावा करने से अक्षम कर दिया गया था।

20. ***एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड (ऊपर)*** निर्धारिती द्वारा दृढ़ता से भरोसा किए जाने को भारतीय तेल निगम लिमिटेड (ऊपर) में दो मामलों पर अलग किया गया था; एक, कि वहाँ एक छूट का सवाल उठाया गया था जो कर के दायित्व को समाप्त नहीं करता है और अगला शब्द हैः'बिक्री के आधार पर आयातित अनुसूचित वस्तुओं या ऐसी आयातित अनुसूचित वस्तुओं के उपभोग से निर्मित वस्तुओं की बिक्री को संशोधन के माध्यम से रोक लगाने के प्रावधान में जोड़ा गया था, बाद में ए. सी. सी. मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि छूट एक रियायत है जिसे कोई भी अधिकार के रूप में तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि उन विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता जिनके तहत इसे दिया जाता है। ओ. एम. सी. के बाद से प्रवेश कर की कोई देनदारी नहीं होने के आधार पर विचार करने के लिए मामले को केवल रिमांड पर लिया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने पेट्रोलियम उत्पादों को बेचा था, इसे पटना के बाहर बेचा था और इस प्रकार पटना की स्थानीय सीमाओं के भीतर माल का उपभोग, उपयोग या बिक्री नहीं की जाती थी।

21. निर्धारिती द्वारा की गई वर्तमान अपील को विफल होना पड़ता है और कानून के प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती के खिलाफ और उत्तरदाताओं के पक्ष में दिया जाता है।

22. अपील खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

राजीव रॉय, न्यायमूर्ति मैं सहमत हूँ।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

सुनील/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।